भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 2171**

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना हेतु समझौता ज्ञापन**

2171. **डा. कविता पाटीदारः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के क्षेत्र में किन–किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन अथवा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा उनमें सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ख) ऐसे सभी समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) साझेदार देशों में भारत के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के परिनियोजन तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों सहित, इन समझौतों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(घ) साझेदार देशों तथा संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ डीपीआई साझेदारियों के समन्वय हेतु कौन–सा संस्थागत ढांचा अपनाया गया है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विस्तार की क्या रूपरेखा है?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पर सरकारों के बीच आपसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) जिसका शीर्षक "डिजिटल बदलाव के लिए बड़े पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग" है, पर अब तक 24 देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य अनुभवों, बेहतरीन तौर–तरीकों और इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी समाधानों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है।

(ख) डीपीआई पर रूपरेखा समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम परिपाटियों का आदान–प्रदान, पायलट समाधानों का विकास, प्राइवेट सेक्टर के साथ संपर्क को आसान बनाने आदि के माध्यम से भागीदार देशों के लाभ के लिए डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है।

(ग) सरकार नियमित रूप से भागीदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों के लिए अध्ययन यात्राओं और तकनीकी बातचीत की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे भारत में प्रमुख डीपीआई संस्थानों, जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) आदि के साथ जुड़ सकते हैं। ये जुड़ाव भागीदार देशों को अपने डीपीआई विकसित करने में भारत के अनुभव का लाभ उठाने और डीपीआई समाधानों के लिए सहयोग के अवसरों और कार्यान्वयन तौर–तरीकों पर चर्चा करने में सक्षम बनाते हैं। हाल के दौरों में श्रीलंका, केन्या, रवांडा, नेपाल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित डीपीआई–आधारित परियोजनाएं वर्तमान में श्रीलंका, म्यांमार, केन्या और गुयाना में कार्यान्वित की जा रही हैं; मॉरीशस और सेशेल्स के साथ डीपीआई परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) डीपीआई पर सहयोग के लिए रोडमैप संबंधित सहयोगी देशों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है, क्योंकि भारत का विकास सहयोग मॉडल मांग पर आधारित है और सहयोगी देशों की ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। सहयोगी देशों के साथ अलग–अलग डीपीआई समाधानों को अंतिम रूप देने का काम उनके अधिकृत प्राधिकारियों के साथ तकनीकी चर्चाओं के ज़रिए किया जाता है; इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

*****